1

परिचय

1991 में भुगतान संतुलन संकट को भारत में सुधार नीति की घोषणा के लिए तात्कालिक विवशता माना गया था। इसका व्यापार नीति के क्षेत्र में, जहाँ आयात लाइसेंस वापस ले लिया गया था, पर तत्काल प्रभाव पड़ा। औद्योगिक नीति के क्षेत्र में, तथाकथित लाइसेंस-परमिट-राज व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। इसने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए अर्थव्यवस्था के खुलने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। वास्तव में, अर्थशास्त्रियों ने 1980 के दशक के बाद उदारीकरण के लक्षणों की पहचान की। उदारीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक विकास में सरकार और बाजार की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण बौद्धिक बहस द्वारा समर्थित थी। कुछ विद्वानों द्वारा सशक्त तरीके से यह तर्क दिया गया कि सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रायः हित समूह शामिल होते हैं जिसके परिणामस्वरुप लोगों के कल्याण को नुकसान पहुंचता है (यहां तक कि एक कल्याणकारी सरकार में भी)। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि एक अनुत्पादक उपांग के रूप में सरकार के 'इंविजिबल फुट' (सरकार की कानूनी और राजनीतिक ताकतों) को एक सशक्त और सभी के लिए समावेशी संस्थान, बाजार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। वस्तुतः, इसके समर्थन में कई अग्रणी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और शैक्षणिक संस्थानों तथा शोधार्थियों के नेतृत्व में दस्तावेजों के बहुत बड़े संग्रह का निर्माण किया गया। 1970 के दशक में जॉन रोंव्ल्स[1], रॉबर्ट नोज़ीक्क[2], जेम्स एम. बुकानन[3], मिल्टन फ्राइडमैन[4], जॉन विलियमसन[5], जगदीश भगवती[6], टी. एन. श्रीनिवासन[7] के प्रकाशनों को उदारीकरण की नीति पर बहस की शुरुआत के रूप में जाना जाता है और अन्य अभी वर्तमान समय तक इस खेमे को बढ़ा रहे हैं। भारत में इसका प्रभाव क्रमागत सरकारों के नीति निरुपण पर पड़ा और इसमें सरकार की भूमिका कम होती गई।

वाशिंगटन कन्सेंसस लोकप्रिय रूप से उदारवादी शोधार्थियों में चर्चित और स्वीकृत किया गया तथा यह वाशिंगटन स्थित संस्थाओं जैसे विश्व बैंक द्वारा (जैसा कि विलियमसन ने खुद स्वीकार किया) पिछले दशकों के आर्थिक सुधारों के आधार पर तैयार हुआ था।[8]

Copyright © 2017. SAGE Publications India Pvt, Ltd.. All rights reserved.

Chalam, K. S.. Arthik Sudhar Aur Samajik Apvarjan : Bhaarat Mein Upekshit Samuhon Par Udareekaran Ka
Prabhav, SAGE Publications India Pvt, Ltd., 2017. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/inflibnet-ebooks/detail.actio
Created from inflibnet-ebooks on 2022-10-12 18:52:19.

भारतीय नीति निर्माताओं ने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुकरण किया। हालांकि, विश्व बैंक ने 1997 की वार्षिक रिपोर्ट में, सरकार की प्रभावी भूमिका को न्यूनतम करने की अपनी वकालत को परिवर्तित कर दिया। यह कहा गया है कि, 'विकास—आर्थिक, सामाजिक और टिकाऊ—एक प्रभावी सरकार के बिना असंभव है।(यह उतरोत्तर देखा गया है कि न्यूनतम असर वाली सरकार के स्थान पर एक प्रभावी सरकार न सिर्फ आर्थिक और सामाजिक विकास का केंद्र है, बल्कि वह एक प्रबंधक से ज्यादा सहभागी और मददकर्ता है।'[9]) भारत ने टिकाऊ विकास लाने वाली विचारधारा के साथ ही विश्व बैंक द्वारा समर्थित उदारीकरण की नीतियों का बड़ी दृढ़ता से अनुसरण किया है। किन्तु अर्थशास्त्री, जिन्होंने न्यूनतम प्रभावी सरकार के लिए तर्क दिये थे, सरकार का ऐसा कोई एक भी सिद्धांत जो भारतीय परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक हो, विकसित नहीं कर पाये हैं। यह अत्यंत बंटा हुआ विषय है क्योंकि पश्चिम के उदारवादी विद्वानों द्वारा जिस रूप में भारत में सरकार की प्रकृति की कल्पना की गयी है तथा कुछ भारतीय विद्वानों और नीति निर्माताओं द्वारा अपनायी गयी है, वह किसी एक 'अदृश्य सुरक्षा एजेंसी' के समान तो प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, विद्वानों और विशेषतया भारतीय विद्वानों के बीच भारत में सत्ता की उत्पत्ति और विशेषताओं को लेकर सर्वसम्मति नहीं पायी जाती है। रोचक बात यह है कि, बहुत ही कम अर्थशास्त्रियों ने भारत के संदर्भ में आर्थिक सिद्धांत विकसित करने में रुचि दिखाई है। इसीलिए, सत्ता में शासक वर्ग के पास सिवाय इसका कोई विकल्प नहीं बचा कि, वे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा सुझाये गये नीति निदानों को जो सरकार की भूमिका को सीमित करती है और सदैव बाजार की भूमिका को बढ़ाती है, का उपयोग करने के लिये मान जायें।

यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय समाजिक वैज्ञानिकों ने भारतीय राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को पश्चिमी नजरिए से समझने की कोशिश की है। असल में, हमारे बहुत से अनुसंधान प्राय: एंग्लो-सैक्सन विद्वानों और जनता को यह बताने के लिए बनाये जाते हैं कि भारत अद्वितीय नहीं है और यह पश्चिम का ही एक हिस्सा है। (दिलचस्प रूप से, भारत में चरम दक्षिणपंथी और वामपंथी विद्वान, सार्वजनिक बहस में जाति की गैर मौजूदगी जैसे कुछ खास मुद्दों पर अब सहमत हुए हैं।) इसीलिए भले ही पश्चिमी अवधारणाओं की सहायता से हमारे समाज के कुछ प्रमुख घटकों को समझाने में कठिनाई महसूस की गई हो फिर भी यहाँ सरकार, अर्थव्यवस्था या समाज का वर्णन करने में उन्हीं अवधारणाओं का प्रयोग होता रहा है। इसका कारण अंग्रेजी और एंग्लो-सैक्सन परंपरा में होने वाला हमारा प्रशिक्षण है।[10] यहाँ तक कि हम अपनी क्रियापद्धति की वैज्ञानिक प्रकृति से समझौता किये बिना विश्लेषण के लिए अपने तरीके विकसित करने में भी सक्षम नहीं हुए हैं। अमर्त्य सेन इसके एक अपवाद है क्योंकि उन्होंने अपने अध्ययन में भारतीय संकल्पनाओं को लागू और

Copyright © 2017. SAGE Publications India Pvt, Ltd.. All rights reserved.

Chalam, K. S.. Arthik Sudhar Aur Samajik Apvarjan : Bhaarat Mein Upekshit Samuhon Par Udareekaran Ka Prabhav, SAGE Publications India Pvt, Ltd., 2017. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/inflibnet-ebooks/detail.actio
Created from inflibnet-ebooks on 2022-10-12 18:52:19.

पुनर्वैधीकरण किया है।[11] इसलिए, हमें अभी भी जाति से संबंधित रोजमर्रा की व्यावहारिक सच्चाई को समझने में समस्या है। अन्य अवधारणाओं के मामले में भी यह सच है। जब तक हम समकालीन मुद्दों जैसे आर्थिक सुधार, सामाजिक उपेक्षा, राष्ट्रीय सरकार, लोकतांत्रिक सराकर आदि की जांच करने के लिए अपने खुद के साधन विकसित नहीं कर लेते तब तक हमें सामाजिक-आर्थिक जीवन की जटिलता को समझने में कठिनाई होगी। इसने हमारे नीति निर्धारण को गंभीर रूप से सीमित किया है। अब भारतीय राज व्यवस्था के गठन पर ध्यान देना अपरिहार्य हो गया है क्योंकि इसने आर्थिक सुधार की नीतियों को तैयार करने और लागू करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सरकार और बाजार

सामाजिक वैज्ञानिकों ने सरकार, बाजार और नागरिक समाज को, भारत में इन संस्थानों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जांच किये बिना ही, स्वायत्त मानना बरकरार रखा है। एंग्लो सैक्सन विद्वानों से अलग जर्मन विद्वान अब भारत की संरचना पर प्रकाश डाल रहे हैं। उदाहरण के लिए, बुर्खार्ड श्नेपल कहते हैं, 'भारत में सरकार की कई व्याख्याएं, सारवादी सर्वेक्षण और संरचनाओं का वर्णन करने की दृष्टि से अत्यंत स्थैतिक और अत्यधिक बंधी हुई हैं; उन्होंने निरंतर होने वाले परिवर्तनों पर भी जिनसे ऐतिहासिक भारतीय साम्राज्य प्रभावित थे, उनपर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक की संरचनात्मक नजरिये से भी नहीं'।[12] कुल्के का अनुसरण करते हुए उन्होंने सरकार के गठन के लिए पांच अलग मॉडलों और 1000 और 1700 ईसा पश्चात के मध्य भारत में सरकार की पहचान की है।[13] कुल्के और श्नेपल ने पाँच पारम्परिक मॉडलों के विषय में चर्चा की है। वे हैं: (क) प्राच्य तानाशाही; (ख) केन्द्रीय रूप से संयोजित या एकात्मक सरकार; (ग) सामंती राज; (घ) वंशगत राज; और (ङ) खण्डीकृत सरकार। श्नेपल ने आगे चर्चा को आधुनिक सरकार के गठन तक और अधिक विस्तृत किया है, जैसा कि समकालीन विद्वानों दुमोंत[14], डर्क्स[15], स्टीन[16], तामबैइह[17], कुल्के[18] और कई अन्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। श्नेपल के अनुसार, 'सरकार, विशिष्ट रूप से, सिर्फ एक केंद्र और कठोर प्रान्तीय सीमाओं के साथ एकात्मक रूप से निर्मित नहीं है। बल्कि यह कई दिशाओं में फैला हुआ राजनीतिक–संस्कारिक संबंधों का जाल है'। उनके सरकार निर्माण के विश्लेषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है राजनीतिक-धार्मिक और संस्कार संबंधित इसकी विषयवस्तु। यद्पि, जिस प्रकार एक पश्चिमी सरकार से भारतीय सरकार में अंतर किया गया, वह सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष तो नहीं है। यह जर्मन विद्वानों द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि भारतीय सरकार के अतीत तथा वर्तमान दोनों में ही इसकी निरंतरता में भारतीय

Copyright © 2017. SAGE Publications India Pvt, Ltd.. All rights reserved.

Chalam, K. S.. Arthik Sudhar Aur Samajik Apvarjan : Bhaarat Mein Upekshit Samuhon Par Udareekaran Ka Prabhav, SAGE Publications India Pvt, Ltd., 2017. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/inflibnet-ebooks/detail.actio
Created from inflibnet-ebooks on 2022-10-12 18:52:19.

विशेषतायें जैसे जनजाति, जाति और क्षेत्र समाहित हैं। आर एस शर्मा ने अपनी नवीनतम पुस्तक में यह कह कर खंडिकृत सरकार के संदर्भ में साउथहॉल[19] की संकल्पना का विरोध किया है कि यह किसी भी अनुभवाश्रित प्रमाणों द्वारा समर्थित नहीं है।[20] ऐसा प्रतीत होता है कि कुल्के और श्नेपल के अध्ययन ने, जिसने संकल्पना के लिये अनुभवाश्रित प्रमाण उपलब्ध कराये, उसने आर एस शर्मा का ध्यान आकर्षित नहीं किया। हालांकि, हम कुल्के और श्नेपल पर भरोसा करते हैं क्योकिं यहाँ हमारा उद्देश्य एक ही है — सरकार या राज व्यवस्था की भारतीय विशेषताओं को देखना।

लेकिन, विश्व बैंक द्वारा, जिस प्रकार की सरकार को उदारीकरण के एजेंडे को आगे ले जाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी माना गया, वह अलग है। विश्व बैंक के अनुसार, सरकार, 'इसके व्यापक अर्थ में यह संस्थाओं का एक सेट है, जिसका तयशुदा प्रान्त और उसकी जनसंख्या, जिसे समाज भी कहते हैं, पर किए जाने वाले वैध नियंत्रण के तरीकों पर अधिकार होता है। सरकार अपने क्षेत्र के भीतर एक सुव्यवस्थित सरकार के माध्यम से नियम बनाने में एकाधिकार रखती है।'[21] यहां, सरकार एक नियम बनाने वाली एजेंसी के रूप में जानी जाती है और इसका आकार सरकारी व्यय और अर्थव्यवस्था के कुल व्यय अथवा निर्गत, जिसे राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, के अनुपात पर निर्भर करता है। यदि पूर्व और बाद के सुधारों की अवधि में भारतीय बजट निर्माण में सार्वजनिक व्यय के मापक को लागू किया जाये, तो यह स्पष्ट होगा कि भारतीय सरकार ने विश्व बैंक के निर्देशों का अनुसरण किया था। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया है कि 1950–51 में केंद्र सरकार के कुल व्यय का जीडीपी से अनुपात 5.2 फीसदी पाया गया था और यह धीरे-धीरे 1980–81 में 16.93 प्रतिशत तक और अन्तत: आर्थिक सुधारों के वर्ष 1990–91 में 20.07 के अधिकतम प्रतिशत पर पहुंच गया। जैसा कि उम्मीद थी, 1990–91 से अनुपात में गिरावट शुरू हो गई जो 2000–01 में 17.25 प्रतिशत से 2007–08 में 16.35 प्रतिशत हो गयी।[22] हालांकि सरकार का आकार सरकारी व्यय के मामले में जीडीपी के पांचवें हिस्से तक ही सीमित है, अर्थव्यवस्था का शेष चौथा-पांचवां भाग सरकार की नीतियों और इसका कॉरपोरेट सेक्टर के साथ संबंधों से संचालित होता है। इसलिए सरकार की प्रकृति और संरचना, आर्थिक सुधार जैसी नीतियों का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण है। अनेक विद्वानों, विशेष रूप से राजनीतिक वैज्ञानिकों ने यह स्थापित करने के लिए कि सरकार न धर्मनिरपेक्ष है और न ही तटस्थ है, अपनी अनवरत पढ़ाई के साथ ही साथ सरकार से जवाब तलब किया। तब आगे यह स्थापित किया गया कि सरकार की संरचना कभी भी प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं थी। केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर, जिन्हें संविधान उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जो कि अभी पांचवाँ भाग है, राज्य विधानसभा और संसद में सीटों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है, समाज के शेष भाग को संसद में उचित अनुपात में प्रस्तुत नहीं

Copyright © 2017. SAGE Publications India Pvt, Ltd.. All rights reserved.

Chalam, K. S.. Arthik Sudhar Aur Samajik Apvarjan : Bhaarat Mein Upekshit Samuhon Par Udareekaran Ka Prabhav, SAGE Publications India Pvt, Ltd., 2017. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/inflibnet-ebooks/detail.actio
Created from inflibnet-ebooks on 2022-10-12 18:52:19.

किया गया है। आंध्र प्रदेश की एक केस स्टडी में यह बताया गया कि, 1998 में राज्य के 42 सांसदों में से अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व 14.2 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का 7.0 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का 6.6 प्रतिशत है और बाकी 62.6 प्रतिशत उच्च जातियों के अंतर्गत आता है।[28] आंध्र प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के लिए आधिकारिक आंकड़ा लगभग 45 फीसदी है। संसद में लगभग 120 सांसद, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के 22.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर भी, वे योजना आयोग द्वारा मंजूर की गयी विशेष घटक योजना जैसी नीतियों पर प्रहार करने में असमर्थ रहे हैं और 2008 के विवादास्पद एससी आरक्षण विधेयक बिल सं LXXIVC को पास होने से नहीं रोक सके। यह सूचित किया गया है कि 2005–10 की बजट योजना में ₹725,37 अरब को विशेष घटक योजना (एससीपी) से हटाकर अन्य कार्यों में लगाया गया है।[24] दूसरी तरफ संसद, कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन में गैस जैसी राष्ट्रीय परिसंपत्ति को जिस तरह से एक निजी व्यवसायिक घराने को सौंप दिया गया है, उसपर चर्चा कर रही है। यह कहा गया कि, 'गैस का उत्पादन भागीदारी अनुबंध रिलायंस इंडिया लिमिटेड (आरआईएल) को सौंप दिया गया जो अपने आप में संदेहास्पद है। जिस तरह से तेल और गैस क्षेत्रों को निजी कंपनियों को दिया गया है वह सार्वजनिक कोष की लूट है'।[25] निजी व्यावसायिक घराने जिनके बारे में संसद और मीडिया में चर्चा हुई थी, भारत के प्रमुख सामाजिक वर्गों में से किसी एक से भी ताल्लुक नहीं रखते थे। वास्तव में, केजी बेसिन में गैस की खोज को इस तथ्य के आधार पर अपने आप में रहस्यपूर्ण कहा गया है कि रिलायंस (अंबानी) की कुल बिक्री, जिससे यह औद्योगिक घराना संबंध रखता है, का अनुपात अनुसंधान एवं विकास पर हुए खर्च से देखने पर, यह निम्नतम में से एक है (0.5 प्रतिशत)।[26] इसके अलावा इस कंपनी की संपत्ति वर्ष 2005–06 में लगभग ₹1639.89 अरब आंकी गई, जबकि 1989–90 में यह महज ₹32.41 अरब थी।[27] शीर्ष 25 व्यापारिक समूहों, जिनमें से कुछ दुनिया में सबसे अमीर माने जाते हैं, में कोई भी ऐसा नहीं है जो भारत में किसी सामाजिक रूप से उपेक्षित जातियों से संबंधित है (तालिका 1.1 देखें)। इसमें कोई अपवाद नहीं कि यह सभी लोग एक या दो प्रभावशाली जातियों से आते हैं, जो कि आर्थिक सुधारों में सरकार के अन्तर्निहित जाति पक्षपात की ओर संकेत करता है।

जाति और बाजार

बाजार एक ऐसी संस्था है जिसे जाति-तटस्थ और सार्वभौमिक होना चाहिए। लेकिन, भारत में इसपर अनेक बंधन हैं। जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, भारत में सरकार के निर्माण में

Copyright © 2017. SAGE Publications India Pvt, Ltd.. All rights reserved.

Chalam, K. S.. Arthik Sudhar Aur Samajik Apvarjan : Bhaarat Mein Upekshit Samuhon Par Udareekaran Ka Prabhav, SAGE Publications India Pvt, Ltd., 2017. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/inflibnet-ebooks/detail.actio
Created from inflibnet-ebooks on 2022-10-12 18:52:19.

एक सामाजिक पक्षपात है क्योंकि राजा या साम्राज्य में से कोई भी स्थानीय पूर्व-अस्पृश्यों से संबंधित नहीं है। हालांकि कुछ शूद्रों और आदिवासियों (जनजाति) ने अतीत में राजाओं का पद वरण किया था, किन्तु उन सभी को 'वर्ण धर्म' का वर्चस्व स्थापित करने हेतु ब्राह्मणवादी अनुष्ठान के माध्यम से क्षत्रियता का ओहदा दे दिया गया था। इसलिए, भारत में सरकार की अद्वितीय विशेषता यह है कि अगर यह एक 'वर्ग सरकार' नहीं है तो यह एक 'जाति सरकार' है। जाति की सर्वव्यापी प्रकृति को सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा दर्शाया गया और यह पाया गया कि इसने बाजार को प्रभावित किया है। भारत में श्रम बाजार पर किये अपने अध्ययन में जेम्स स्कोविले ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह विभाजित है।[28] उन्होंने 'श्रम बाजार विभाजन में स्थिरता को बनाए रखने की अभेद्यता, स्थायित्व और अनिवार्यता को साबित कर दिया है।' दो दशक पहले 'शिक्षा और कमजोर वर्गों' पर हमारे एक अध्ययन में हमने देखा कि समान योग्यता और अनुभव के बावजूद भी एससी स्नातकों ने दूसरों की तुलना में कम मजदूरी प्राप्त की।[29] हाल ही में, विश्व बैंक के विद्वानों मैत्रेयी बोर्डिया दास और पूजा वासुदेव दत्त ने भारत में मजदूरी भिन्नता पर अपने अध्ययन में, जाति को इसमें एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में चिह्नित है। उन्होंने देखा कि नियमित और आकस्मिक दोनों प्रकार के कार्यों में एससी और सामान्य जाति के बीच मजदूरी में अंतर है।[30] जाति विशेषताओं में विभिन्नता होने की वजह से यह अंतर 59 फीसदी तक है। दशक के सबसे बड़े घोटालों में से एक माने जाने वाले सत्यम घोटाले को 'एक घोटाले की जाति' करार दिया गया है। यह पार्थसारथी द्वारा इस प्रकार वर्णित किया गया है:

> सत्यम, मेटास और नागार्जुन फायनेंस- तीन कंपनियाँ वित्तीय अनियमितताओं में शामिल हैं... जिन्हें राजू वंश के सदस्यों द्वारा संचालित और नियंत्रित किया जा रहा था ...राजू के स्वामित्व वाली अन्य कंपनियों और सरकारी संस्थानों के साथ इसका संबंध था। इस प्रकार का संबंध पूंजीवादी पश्चिम के लिये असामान्य नहीं है... एक लंबी समयावधि के दौरान जटिलता से जुड़ी हुई जाति और राजनीतिक नेटवर्क का निर्माण होना[13]।

हालांकि हमारे कॉर्पोरेट जगत में इस प्रकार के कई जाति नेटवर्क काम करते हैं, परन्तु ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में कारोबार की छिपी सफलता के एजेंडे को प्रकट करने के लिए यह सामने आया है।

हालांकि भारत में सभी एससी और उपेक्षित समूहों के साथ श्रम, पूंजी और भूमि के बाजारों में भेदभाव व्यावहारिक अनुभवों में देखा गया है, किन्तु विद्वानों द्वारा अब अनुभवजन्य साक्ष्यों के साथ इसका पुष्टिकरण हुआ है। यद्पि दो महत्वपूर्ण संस्थान, सरकार और बाजार, जाति जैसे अनूठे भारतीय चरित्र को दूषित करते ही पाए गये हैं। हालांकि, 1991 में जब आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई तब इन दो महत्वपूर्ण पश्चिमी अवधारणाओं

Copyright © 2017. SAGE Publications India Pvt, Ltd.. All rights reserved.

Chalam, K. S.. Arthik Sudhar Aur Samajik Apvarjan : Bhaarat Mein Upekshit Samuhon Par Udareekaran Ka Prabhav, SAGE Publications India Pvt, Ltd., 2017. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/inflibnet-ebooks/detail.actio
Created from inflibnet-ebooks on 2022-10-12 18:52:19.

ने हमारे नीति निर्माताओं के मन को इस तरह से बेचैन कर दिया कि उन्होंने भारतीय स्थिति के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने केवल भुगतान संतुलन में आये तात्कालिक आर्थिक संकट से उबरने के लिए तथाकथित समष्टि आर्थिक नीतियों का अनुकरण किया। इसलिए, जब 2005 में सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया, तब नीति निर्माताओं को इन विधियों की सीमाओं का एहसास हुआ था।

वर्ष 2009, समकालीन सामाजिक आर्थिक जीवन के कई क्षेत्रों में सामंजस्य और पुनर्विचार करने वाले वर्ष के रूप में हमारे सामने आया। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी ने एक लोकप्रिय पत्रिका, द *इकॉनोमिस्ट*, में 'अर्थशास्त्र के साथ क्या गलत हुआ' (व्हॉट वेंट रॉन्ग विद इकॉनोमिक्स) प्रकाशित करने को प्रेरित किया। पॉल क्रुगमैन का उद्धरण देते हुए यह कहा गया है, 'पिछले लगभग 30 वर्षों में समष्टि अर्थशास्त्र सबसे अच्छा लेकिन असाधारण रूप से व्यर्थ और सबसे बुरा लेकिन सकारात्मक रूप से हानिकारक था।[32] तदनुसार, जनरल ने समर्थन करते हुए कहा कि अर्थशास्त्रियों को अपने खास बंद कमरों से बाहर आना चाहिए—समष्टि अर्थशास्त्रियों को वित्त को समझना चाहिए, और वित्त के प्रोफेसरों को **'जिस संदर्भ में बाजार काम करता है'** उसके बारे में गहराई से मनन करने की जरूरत है (इस पर ज़ोर दिया गया है)।[33] दूसरे शब्दों में, उल्लास के साथ जो सुधार दुनिया भर में शुरू किए गए थे उनके प्रति बौद्धिक समुदाय के बीच एक थोड़ी-बहुत स्वीकृति तो मिलती प्रतीत होती है। लेकिन, बिना किसी भी व्यावहारिक प्रमाण के जनता के बीच गलतियों या खामियों को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है (हमारे अपने अनुभव से)।

भारत में आर्थिक सुधार इस आधार के साथ शुरू किया गया था कि सरकार 'प्रभावी' है और बाजार तटस्थ और 'सक्षम' है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय संदर्भ में इन दोनों संस्थानों की अनेक सीमाएं हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों में भी, अब यह साबित हो गया है कि बाजार अपूर्ण और हेरफेर करने वाले हैं। हमारे समाज में जहाँ लोकतांत्रिक पुनरुत्थान में जाति को फिर से प्रस्तुत किया जाने लगा, प्रमुख जातियों को इसका स्पष्ट एहसास हो गया था और उन्होंने खुद को व्यापार तक सीमित कर लिया (जब उनकी संख्या भविष्य में राजनीतिक गतिविधि में हेरफेर करने के लिए बेहद कम है)। लिहाजा, इन तेजी से बढ़ते जाति समूहों ने सुधारों के माध्यम से मिले मौकों का बखूबी इस्तेमाल किया, जिससे पारम्परिक रूप से उपेक्षित समूह समाज से अलग होते गए। ऐसा हमारी समाज को लेकर गलत और आधी-अधूरी समझ तथा समष्टि अर्थशास्त्र की नीतियों की गलत मान्यताओं के कारण हुआ है। आगे के पन्नों में उपेक्षित समूहों और पारंपरिक जातियों पर सुधारों के प्रभाव की व्यावहारिक वास्तविकता का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

Copyright © 2017. SAGE Publications India Pvt, Ltd.. All rights reserved.

Chalam, K. S.. Arthik Sudhar Aur Samajik Apvarjan : Bhaarat Mein Upekshit Samuhon Par Udareekaran Ka Prabhav, SAGE Publications India Pvt, Ltd., 2017. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/inflibnet-ebooks/detail.actio
Created from inflibnet-ebooks on 2022-10-12 18:52:19.

परिशिष्ट

तालिका A1.1
शीर्ष 25 व्यापारिक समूहों की संपत्तियाँ, 2005–06

			संपत्तियाँ (100 करोड़ = 1 अरब)		
श्रेणी	*श्रेणी 1990*	समूह/घराना	*1989–90*	*1991–92*	2005–06
1	3	रिलायंस (अम्बानी)	3,241	9,167	163,989
2	2	टाटा	6,851	15,564	101,219
3	1	बिरला	7,235	13,917	67,544
4	26	एस्सार (रूइआ)	437	1,898	44,949
5	15	आई.टी.सी.	742	4,047	30,012
6		ओम प्रकाश जिंदल		635	26,886
7	28	हिंदुजा (अशोक लेलैंड)	422	1,277	23,197
8		भारती टेलीकॉम		29	21,808
9		स्टिरलाइट इंडस्ट्रीज		2,480	19,457
10	9	लार्सेन एंड टुब्रो	1,130	3,199	17,589
11	7	बजाज	1,228	1,908	16,994
12	22	गोयनका	570	3,583	16,151
13		इस्पात (मित्तल)		1,092	15,142
14	21	महिंद्रा एंड महिंद्रा	620	1,223	14,947
15	11	टी.वी.एस. एवेंजर	929	1,582	14,176
16	12	यूनिलीवर (एफ)	925	3,368	13,669
17	एसएलयू	जयप्रकाश	484	1,164	12,845
18		वीडियोकॉन		873	11,373
19		विप्रो		103	9,595
20		इन्फोसिस टेक्नो. लिमी.		8	9,114
21		जेटएयरवेज (भारत) लिमि.			9,067
22	4	सिंघानिया	1,938	2,952	8,356
23		मोसेर बेयर (एफ) ग्रुप			8,178
24	5	थापर	1,782	2,665	8,010
25		भाई मोहन सिंह		539	7,999

स्रोत: सुरजीत मजूमदार, 'क्रोनी कैपिटलिजम एंड इंडिया'।
नोट: 1989–90 के लिये; शेष के लिये, सीएमआईई, प्रोवेस डाटाबेस।

Copyright © 2017. SAGE Publications India Pvt, Ltd.. All rights reserved.

Chalam, K. S.. Arthik Sudhar Aur Samajik Apvarjan : Bhaarat Mein Upekshit Samuhon Par Udareekaran Ka Prabhav, SAGE Publications India Pvt, Ltd., 2017. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/inflibnet-ebooks/detail.actio
Created from inflibnet-ebooks on 2022-10-12 18:52:19.

टिप्पणियां

1. John Rawls, *A theory of Justice* (Oxford: Oxford University Press, 1999). इन्होंने राज्य को महत्व दिया है क्योंकि परिणामों पर इसका नियंत्रण रहता है और यह व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से ऊपर उठकर असहमतियों को सुलझाता है। वास्तव में यूएस में सिविल राइट्स एक्ट के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर आधारित जेम्स सैमुअल कोलमेन की मशहूर कोलमेन रिपोर्ट (1966) में भी पश्चिम में बौद्धिक वाद-विवाद की शुरुआत का उल्लेख किया गया था। हालांकि भारत में भी मिलते-जुलते प्रावधान थे, लेकिन पश्चिम की तरह यहां कोई वाद-विवाद नहीं हुआ जो यहां कि बौद्धिक गरीबी को दर्शाता है।
2. Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia* (New York: Basic Books, 1977). इनके मुताबिक राज्य एक अदृश्य एजेंसी बनने की प्रक्रिया के तहत एक सुरक्षात्मक एजेंसी के रूप में उभरता है। अगर इस तर्क को माना जाए तो राज्य एक निजी प्रभावशाली फर्म बन जाता है।
3. James M. Buchanan, *The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan* (Chicage: University of Chicago Press, 1977). राज्य दोहरी भूमिका निभाता है। पहली संवैधानिक आदेशों का पालन और दूसरी सार्वजनिक उत्पादों की पूर्ति। यह दोहरापन ही अपने आपमें भ्रमित करने वाला है।
4. Milton Friedman, *Capitalism and Freedom* (Chicage: University of Chicago Press, 2002). मिल्टन ने तर्क दिया कि उदार सरकार को कानून व व्यवस्था और संपत्ति अधिकारों को लागू करना चाहिए। कई अच्छी चीजें बाजार से आती हैं न कि राज्य से।
5. John Williamson, *What Washington Means by Policy Reforms* (Washington: Institute of International Economics, 1989).
6. Jagdish Bhagwathi, *In Defence of Globalization* (New York: Oxford University Press, 2004).
7. T.N. Srinivasan and S.D. Tendulkar, *Reintegrating India with World Economy* (Washington D.C.: Peterson Institute, 2003) and T.N. Srinivasan, *Eight Lectures on India's Economic Reforms* (New Delhi: Oxford University Press, 2000).
8. John Williamson, *What Should the World Bank Think about the Washington Consensus* (Washington D.C.: Peterson Institute, 1999).
9. The World Bank, *The World Development Report 1997: The State in a Changing World* (New Delhi: Oxford University Press, 1997).
10. K.S. Chalam, 'Rethinking Social Sciences', *Economic and Political Weekly*, 15 March 2002; 'Social Science Research in India: The Social Context', *Economic and Political Weekly*, 28 September 2002.
11. Amartya Sen, *The Argumentative Indian* (New Delhi: Penguin Books, 2005); Amartya Sen, *The Idea of Justice* (New Delhi: Penguin Books, 2009).
12. Burkhard Schnepel, *The Jungle Kings: Ethno Historical Aspects of Politics and Ritual in Orissa* (Delhi: Manohar, 2002), 79.

Copyright © 2017. SAGE Publications India Pvt, Ltd.. All rights reserved.

Chalam, K. S.. Arthik Sudhar Aur Samajik Apvarjan : Bhaarat Mein Upekshit Samuhon Par Udareekaran Ka Prabhav, SAGE Publications India Pvt, Ltd., 2017. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/inflibnet-ebooks/detail.actio
Created from inflibnet-ebooks on 2022-10-12 18:52:19.

13. H. Kulke, *The State in India 1000–1700* (New Delhi: Oxford University Press, 1995).
14. L. Dumont, *Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications* (Chicago: University of Chicago Press, 1980).
15. N.B. Dirks, *The Hollow Crown: Ethno History of an Indian Kingdom* (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).
16. B. Stein, *Peasant State and Society in Medieval South India* (New Delhi: Oxford University Press, 1980).
17. S.J. Tambaiah, *Culture, Thought and Social Action: An Anthropological Perspective* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).
18. Kulke, *The State in India 1000–1700*.
19. A. Southhall, 'The Segmentary State in Africa and Asia', *Comparative Studies in Society and History*, January 1988.
20. R.S. Sarma, *Rethinking India's* Past (New Delhi: Oxford University Press, 2009).
21. The World Bank, *The World Development Report 1997*, 20.
22. Government of India, *Economic Survey 2008–09* (New Delhi: Ministry of Finance, 2009), A-3 and A-39.
23. K. Ramamurthy and D. Surannaidu, *Parties, Elections and Mobilisation* (New Delhi: Anmol Publications, 2001).
24. Government of India, *Expenditure Budget Vol I & II 2009–10* (New Delhi: Planning Commision, 2009). उपेक्षितों की हितों की रक्षा के लिए बनाए गए कल्याण राज्य के सिद्धांत की आड़ में राज्य के संसाधनों के प्रमुख स्रोतों को कुछ प्रभावशाली जातियों को दे दिया गया जबकि दलित और अन्य के हाथ कुछ टुकड़े ही लगे।
25. *The Hindu*, 'Center's Stand on RIL-RNRL Dispute'; *The Hindu*, 21 July 2009, Tuesday, p. 14; *The Times of India*, 'K.G. Gas Belongs to Government not Ambanis, Says Deora', *The Times of India*, 13 July 2001, 19.
26. Surajit Mazumdar, 'Crony Capitalisation in India: Before and After Liberalization', working paper No. 4, 2008, ISIS, New Delhi, 22. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दावा किया कि उसने खोज पर 450 बिलियन खर्च किये। लेकिन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार द्वारा पेश सबूत इसका समर्थन नहीं करते क्योंकि मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में रिलायंस के ऑडिट के रिकॉर्ड पेश नहीं किये। (वार्ता, 9 अगस्त 2009 और द हिंदू, 11 अगस्त 2009).
27. Mazumdar, 'Crony Capitalism and India: Before and After Liberalization'.
28. James Scoville, 'Labour Market Underpinnings of a Caste Economy: Foiling the Coase Theorem', *American Journal of Economics and Sociology*, October 1996.
29. K.S. Chalam, *Education and Weaker Sections* (New Delhi: Inter-India Publications, 1988).

Copyright © 2017. SAGE Publications India Pvt, Ltd.. All rights reserved.

Chalam, K. S.. Arthik Sudhar Aur Samajik Apvarjan : Bhaarat Mein Upekshit Samuhon Par Udareekaran Ka Prabhav, SAGE Publications India Pvt, Ltd., 2017. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/inflibnet-ebooks/detail.actio
Created from inflibnet-ebooks on 2022-10-12 18:52:19.

30. Maitriyi Bordia Das and Puja Vasudeva Dutta, 'Does Caste Matter for Wages in the Indian Labour Market', Social Development Unit, The World Bank, 18 December (Washington D.C., 2007).
31. Parthasarathy, 'The Caste of a Scam: A Thousand Satyams in Making', reproduced in *The South Asian*, 17 February 2009.
32. *The Economist*, 'What Went Wrong with Economics', *The Economist*, 18–24 July 2009. Also see pp. 58–63.
33. *The Economist*, 'What Went Wrong with Economics'.

Copyright © 2017. SAGE Publications India Pvt, Ltd.. All rights reserved.

Chalam, K. S.. Arthik Sudhar Aur Samajik Apvarjan : Bhaarat Mein Upekshit Samuhon Par Udareekaran Ka Prabhav, SAGE Publications India Pvt, Ltd., 2017. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/inflibnet-ebooks/detail.actio
Created from inflibnet-ebooks on 2022-10-12 18:52:19.